**राज्यपाल सचिवालय**

**राज भवन जयपुर**

**जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दें**

**केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए**

**आवंटित राशि का समुचित का समुचित सदुपयोग हो - राज्यपाल**

जयपुर/बाड़मेर, 10 अगस्त। राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने, गांव गरीब के लोगों को विकास कार्यों का समयबद्ध लाभ पहुंचाने और कल्याण योजनाओं की राशि का जन हित में समुचित सदुपयोग किए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने बाड़मेर जिले में पानी की महत्ता को देखते हुए जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता से करवाया जाने का भी आह्वान किया। उन्होंने बारिश की एक एक बूंद -बूंद को सहेजने पर जोर देते हुए बाड़मेर रिफाइनरी उत्पादों और खनन क्षेत्र से स्थानीय लोगों के रोजगार सृजन के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता जताई।

राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे शनिवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला परिषद सभागार में केन्द्र सरकार प्रायोजित योजनाओं एवं अन्य विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे।

राज्यपाल श्री बागडे ने कहा कि मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के बजट का सदुपयोग करते हुए वृहद स्तर जल संरक्षण के कार्य करवाए जाएं ।उन्होंने कहा कि गांव का पानी गांव में रहना चाहिए ।इसके लिए व्यापक इंतजाम किए जाएं । राज्यपाल ने केन्द्र सरकार प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के समस्त लाभार्थियों के नाम आगामी एक माह में उनके आवास पर प्रदशित करने के निर्देश दिए । उन्होंने राजीविका से जुडी महिलाओं को उनके उत्पादों के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया ।

उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के के विश्नोई ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं को स्थानीय स्तर मेला, हाट बाजार आयोजित करने एवं प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाले मेलों में भिजवाने की जरुरत जताई। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि शिव क्षेत्र के जल जीवन मिशन सर्वे से वंचित गांवों एवं ढाणियों को जोड़ा जाने का आग्रह किया ।चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल समेत अन्य जन प्रतिनिधियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधित सुझाव दिए।

समीक्षा बैठक में राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे ने केन्द्र सरकार प्रायोजित योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन से बाड़मेर जिले में आधारभूत सुविधाओं के विकास के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना विकास की स्थिति एवं आवश्यकता, भौगोलिक परिस्थितियों एवं संसाधनों की कमी से प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक स्त्र पर सुधार के लिए चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रम, स्थानीय नागरिकों के रोजगार के लिए पलायन रोकने की दिशा में किए गए प्रयासों तथा हिन्दू पाक विस्थापितों की स्थिति एवं उनके उत्थान संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रजेटेंशन के जरिए उनसे संबंधित विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया।

---